शोध मंथन, Impact Factor 6.726 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255 (e): 2454-339X
Vol. X, No.II, pp (755-759) April - June 2019

''भारत–ईरान सम्बन्धों पर अमेरिकी नीति का प्रभाव''

डॉ रेखा रानी
राजनीति विज्ञान विभाग,
पोस्ट डॉक्टोरल फैलोशिप
Email:starjistar@gmail.com

सांराश

भारत ने दृढ़ता पूर्वक ईरान से परम्परागत सभ्यमूलक सम्बन्धों को दोहराया है। वह भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला तीसरा बड़ा देश है। अमेरिका ने मांग की है कि भारत ईरान से तेल खरीदना बन्द करे। सबसे पहले भारत ने घोषणा की कि भारत एकतरफा प्रतिबन्धों को नहीं मानता है और केवल उन्ही प्रतिबन्धों को लागू करेगा जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाये जायेगें।

भविष्य बहुत अनिश्चित है। चीन शायद ही अमेरिकी प्रतिबन्धों का पालन करें। भारत के सामने बहुत सीमित विकल्प है अगर भारत अमेरिकी नेतृत्व के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो यह उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के साथ–साथ उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा झटका होगा।

राष्ट्रीय मुद्रा के उपयोग से व्यापार, बीमा और शिपिंग करने के लिये समझौते करने निःसन्देह भारत मुश्किल स्थितियों में फंसा हुआ है। लेकिन उसे जैसे अन्य विकल्पों को तलाशने की जरूरत है। ऐसा शायद ही किसी देश में होता है, जो स्वयं को विश्वशक्ति मानता है और राजनीतिक स्वायत्ता का दावा करता है। निश्चित रूप से भारत को अपने हितों का पालन करना चाहिये जो अन्तराष्ट्रीय राजनीति का मार्ग है। लेकिन सबसे पहले उसे यह तय करना होगा कि वास्तव में उसके सर्वोत्तम हित क्या हैं।

प्रस्तावना

मूलबिन्दु

1. अमरीका ने भारत से कहा कि वो ईरान के साथ अपने सम्बन्धों की समीक्षा करे और चार नवम्बर तक ईरान से तेल का आयात पूरी तरह से बंद कर दे।
2. भारत चीन के बाद ईरान से कच्चा तेल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा खरीददार है। वहीं ईरान अपना दस प्रतिशत तेल निर्यात सिर्फ भारत को करता है।
3. ईरानी अखबार तेहरान टाइम्स ने लिखाा है कि साल 2012 से 2016 के बीच ईरान के खिलाफ अमेरीका और यूरोपीय संघ के प्रतिबन्धों के बावजूद ईरान भारत को कच्चा तेल बेचने वाला सबसे बड़ देश था।
4. इसी साल फरवरी में ईरानी राष्ट्रपति हसर रुहानी के दिल्ली दौरे के बाद ईरान में पेट्रोलियम, गैस और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ है।

5. भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह का निर्माण भी कर रहा है जो अफगानिस्तान के लिए एक नया रास्ता भी खोलेगा।
6. पूर्व अमरीकी राष्ट्रति बराक ओबामा के दौर में अमरीका ने भारत को ईरान से तेल खरीदने और चाबहार बंदरगाह के निर्माण के मामले में छूट दे रखी थी।

भारत और ईरान प्राचीन सभ्यतायें है। सदियों से सभ्यता एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध मूल्य एवं परम्परायें एक होने के कारण भारत व ईरान ने अनेक क्षेत्रों में एक दूसरे पर प्रभाव डाला है। ईरान के साथ सम्बन्धों को लेकर भारत को अपनी घरेलू राजनीति की संघर्षपूर्ण आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है चूंकि हाल के वर्षों के दौरान भारत के वैश्विक महतव में वृद्धि हुयी है और अमेरिका के साथ इसके सम्बन्ध मजबूत हुये है। इस कारण यह संघर्ष और अधिक प्रासांगिक हो गया है।

भारत और ईरान सम्बन्धों का आधार बहुत नाजुक रहा है और यह 70 और 80 के दशक के अंतिम दौर में आये परिवर्तनों को झेल पाने में असमर्थ था क्योंकि वर्ष 1991 की ईरानी क्रान्ति के माध्यम से पैदा हुयी राजनीतिक अनिश्चितायें बरकार थी। 1990 में भारत–ईरान सम्बन्धों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला। अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में आए बदलाव में अपनी–अपनी विदेश नीति को पुनः परिभाषित करना शुरू किया ईरान को वैश्विक रूप से अलग करने का अमेरिका का प्रयास, सोवियत संघ का विघटन, जिसके कारण अनेक मध्य एशियाई गणतन्त्रों का उदय हुआ और अयोतुल्ला खोमानी की मृत्यु जिससे ईरान में इस्लामी कट्टरवाद के समर्थन में कमी आयी इस कारण भारत और ईरान के बीच सम्बन्धों के पुर्नमेल होने में भूमिका निभाई।

भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने 1993 में ऐतिहासिक ईरान का दौरान किया 1979 की इस्लामी क्रान्ति के बाद ईरान का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। इस दौरे के बदले 1995 में रफसजानी ने भारत का राजकीय दौरा किया। भारत ने गणतन्त्र दिवस समारोहों में वर्ष 2003 में खोमानी को मुख्य अतिथि बनाकर भारत–ईरान के बीच के ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को न केवल उजागर किया बल्कि यह संकेत भी दिया कि ईरान क्षेत्रीय, राजनीतिक एवं सुरक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में एक अहम ताकत है। मई 2016 में मौजूदा भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने ईरान का दौरा किया जिसमें द्विपक्षीय व्यापार और ऊर्जा विकास जैसे मुद्दों को केन्द्र में रखा गया।

2003 के ईरानी राष्ट्रपति के भारत दौरे के बाद ही ईरान के साथ आर्थिक रिश्तों ने जो पकड़ना शुरू किया इसमें तेल के व्यापार ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। 2008–09 में आयात के 9.5 प्रतिशत की वृद्धि से यह मुमकिन हुआ कि ईरान भारत को दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला देश बन गया है।

भारत–ईरान में 08 बिलियन डॉलर के निवेश से चाबहार बंदरगाह के निर्माण कार्यों में जोरो–शोरों के साथ लगा हुआ है। 03 दिसम्बर, 2017 को चाबहार बन्दरगाह मध्य एशिया को भारत–अफगानिस्तान ईरान के लिये एक बड़े बाजार के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखता है। रक्षा क्षेत्र की बात की जाये तो भारत–ईरान के बीच 2001 में एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर हुये

थे। चाबहार बन्दरगाह के विकास के साथ ही दोनों देश जल मार्ग का विकास व्यापार के लिये खुला रखकर करना चाहता है, इसके लिये भारत–ईरान की नौ–सेनाओं अभ्यास में निवेश भी प्रस्तावित है।

भारत व ईरान दोनों को आर्थिक व सामरिक फायदे है भारत को ईरान का तेल सउदी–अरब के मुकाबले काफी सस्ते दामों पर मिलता है। ईरान भारत के साथ रूपये में व्यापार करने पर सहमत है सउदी–अरब व पाकिस्तान की मित्रता का जवाब देने के लिये भी भारत और ईरान को एक–दूसरे की जरूरत है भारत की विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज ने भी पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि भारत सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संगठन के प्रतिबन्धों को मानता है किसी देश के प्रतिबन्धों को नहीं इसलिये भारत–ईरान के साथ सम्बन्ध जारी रखेगा।

अमेरिकी नीति प्रभाव

शीत युद्ध के बाद की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अमेरिका के सम्पूर्ण दबदबे ने रूस, चीन, भारत, ईरान जैसे सभी प्रमुख देशों को बैचेन कर रखा है यद्यपि किसी भी रूप में अमेरिकी दबदबे की चुनौती देने के पक्ष में वे नहीं है उन्होंने अपने द्वि–पक्षीय सम्बन्धों को बेहतर बनाने के लिये अनेक प्रयास किये हैं यद्यपि इस प्रक्रिया में रूस–चीन और भारत जैसे देशों का अमेरिका के साथ सम्बन्धों में हाल दिनों में नाटकीय ढंग से सुधार आया है लेकिन ईरान के प्रति अमेरिका का रख वैमनस्यपूर्ण ही रहा है। सन् 1991 को खाड़ा युद्ध में ईराक की हार के पश्चात् खाड़ी में अमेरिकी विदेशी नीति को केन्द्र ईरान तथा इस्लामिक क्रान्तिकारी विचारों को रोकने की ओर उन्मुख हो गया है। ईरान द्वारा फारस की खाड़ी में अमेरिकी हितों को उल्लेखनीय चुनौती देने की क्षमता के बावजूद ईरान के लिये स्थिति को बहुत खराब बना दिया। 11 सित्मबर, 2001 के पश्चात् ईरान को भी ''एक्सिस ऑफ इविल का सदस्य नामित कर दिया जिसे अमेरिकी इस्लामिक आतंकवाद का समर्थक मानता है।

ईरान के साथ हुये परमाणु समझौते ''जे0सी0पी0ओ0 सन्धि'' को अमेरिका द्वारा भारत समेत अन्य देशों पर ईरान के साथ सम्बन्ध तोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। भारत के दौरे पर आयी हुई संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि **निक्की हेली** ने कहा कि– ''04 नवम्बर, 2018 से पहले ईरान से तेल खरीदना भारत बन्द करें एवं ईरान के साथ सम्बन्ध समाप्त करने पर गंभीरतापूर्ण विचार करें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प इस बात को कई बार दोहरा चुके है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले सभी कम्पनियों पर अमेरिका कड़े प्रतिबन्ध लगायेगा 2011 में भी अमेरिका ने कड़े प्रतिबन्ध लगाये थे। 2011 में ईरान पर प्रतिबन्ध लगने के बाद व्यापार हेतु डॉलर पर पाबन्दी लगी होने की वजह से भारत और ईरान ने रूपये में व्यापार करना शुरू किया अमेरिका के अलावा यूरोप के अन्य देश जे0सी0पी0ओ0ए0 सन्धि का अभी भी सम्मान कर रहे है इस सूरत में व्यापार हेतु भारत रूपये के अलावा यूरो करंसी का इस्तेमाल कर सकता है।

तेहरान टाइम्स हाल के दिनों अपनी रिफाइननियों से कहा कि वो नवम्बर में ईरान से तेल की सप्लाई होने के लिये खुद को तैयार रखे, तेल की कीमत पहले से बढ़ रही है और ईरानी तेल की सप्लाई बन्द ह ोने से कीमतों का बढ़ना तय है डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद

भारत में काफी उम्मीदें पैदा हुई थी कि दोनों जगह दक्षिणपंथी नजरिया वाली सरकारें होने से दोनों देशों के रिश्तों में जबरदस्त बेहतरी आयेगी लेकिन वो शुरूआती जोश अब ठण्डा पड़ चुका है। ट्रम्प के कई फैसलों से भारत को नुकसान पहुंचा है। मई 2017 में डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत को दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले देशों में से एक बताया था उन्होंने कहा था कि "पेरिस समझोते के तहत अमेरिका खरबों डॉलर दे रहा है। जबकि रूस, चीन और भारत जैसे देश प्रदूषण फैलाने वाले कुछ नहीं दे रहे है। हाल में अमेरिका ने भारत सहित दुनिया के कई देशों से कहा था कि वे 04 नवम्बर तक ईरान से कच्चे तेल का आयात रोक दे। ऐसा न करने पर उसने इन देशों पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने की चेतावनी दी थी।

भारत के लिये ये एक मुश्किल स्थिति है। एक तरफ ईरान से उसके सम्बन्ध गहरे है और दूसरी और वो ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका के अलग होने के फैसले से भी सहमत नहीं है। चीन और तुर्की ने अमेरिका की पांबदियों को अस्वीकार कर दिया है जबकि यूरोपीय देशों ने कहा है कि वो ईरान से परमाणु समझौते को बरकार रखेंगें।

भारत ने ईरान और अमेरिका दोनों के साथ अपने सम्बन्धों को सावधानीपूर्वक सन्तुलित करने की कोशिश की है फिर भी भारी अमेरिका के दबाव के चलते विशेष रूप से अमेरिकी–भारत नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के और नजदीक हुआ है किन्तु घरेलू भारी दबाव बने हुये है जो भारत को ईरान से रिश्ते को पूरी तरह खत्म होने से रोकते है।

चूंकि अमेरिका और भारत के बीच तनाव बढ़ गये है अतः भारत की विदेश नीति में भी वे तनाव देखने को मिल रहे है। भारतीय राजनीतिक स्पेक्ट्रम के नाम दक्षिणपंथी दलों के परमाणु समझौते को लेकर दबाव के चलते भारत सरकार काफी दबाव में जैसे–जैसे अमेरिका कांग्रेस ने ईरान को जबावदेह परमाणु शक्ति के रूप में भारत के भरोसे के लिये टेस्ट देश बनाया वैसे–वैसे नई दिल्ली स्थित आलोचक स्वतन्त्र विदेश नीति की बोगी उठाने के लिये स्वयं को ताकतवर महसूस करने लगे। भारत के राजनीतिक एवं सामरिक संभ्रातों के कुछ तबको के लिये इसका मतलब था सभी वैश्विक मंचों पर अमेरिका का विरोध करना।

भारत ईरान सम्बन्धों पर अमेरिका का ध्यान उन ठोस वास्तविक्रेताओं की तुलना में अत्याधिक गैर, आनुपातिक रहा है। जो इस रिश्ते को चोट पहुंचती है जिसका परिणाम क्षेत्रीय राजनीतिक वास्तविक्रेताओं के प्रत्युत्तर में घरेलू राजनीति की अनिवार्यताओं के प्रति अधिक दिखाई देता है भारत ने हाल के दिनों में चीन और रूस के साथ सम्बन्ध बढ़ाने की कोशिश की है भारत के इस कदम से अमेरिका की नाराजगली और बढ़ेगी। भारत–चीन और रूस के जैसे ताकतवर भी नही है कि अमेरिका से टकराव का रास्ता चुन ले। वो अपने आप को भले ही क्षेत्रीय ताकत या आर्थिक पॉवर हाउस समझता हो लेनिक अमेरिका के नजदीक उसकी हैसियत एक जूनियर पार्टनर से ज्यादा नहीं है।

भारत को ईरान के मामले पर जल्द ही कोई फैसला करना होगा। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ईरान से तेल की खरीद बंद करना देश के हित में नहीं होगा लेकिन क्या भारत

अमेरिका की पाबंदिया का सामना करने के लिये तैयार है या फिर वो पाबंदिया के जरिये ईरान को आर्थिक तौर पर तबाह करने के लिये अमेरिका, इजराइल और सउदी–अरब जैसे ईरान विरोधी देशों के साथ खड़ा होगा।

भारत के सामने ये बहुत बड़ी कूटनीतिक, आर्थिक और नैतिक चुनौती है भारत के पास वक्त कम और दबाव बहुत ज्यादा है।

संदर्भ ग्रन्थ

1. Robin Wright, *'The Iran Primer : Power, Polices and U.S. Policy'*, United State Institute of Perce Press, Washington, U.S.A.
2. Narain D. Batra, *'Complicated Relationship : India Needs Both Isreals and Iran,'* Narwich University, U.K. 19 February, 2012.
3 तिवारी, ओम प्रकाश, *'राष्ट्रीय सुरक्षा'*, ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003।
4 सिंह, योगेन्द्र पाल, *'भारत विदेश नीति'*, एक अध्ययन आगरा, 19963।
5 मिश्रा, डॉ0 कृष्ण कुमार, *'भारतीय उप महाद्वीप के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका का दृष्टिकोण*, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली।
6 सक्सेना, डॉ0 बनारसी प्रसाद, *'अमेरिका का इतिहास'*, दिल्ली विश्वविद्यालया, दिल्ली, 1992।